उत्पादन में वृद्धि करने पर रहा है। कृषकों को नकदी फसलों की खेती करने के लिये प्रोत्साहन किये जाने के उद्देश्य से सरकार ने खरीफ में छूटी परती भूमि के उपयोग, अन्तःवर्ती फसल पर बल देने तथा उत्तरवर्ती फसल पद्धति को प्रोत्साहित किया है।

fodder banks in drought prone areas

2429. DR. NARREDDY THULASI REDDY : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government propose to establish Fodder Banks in drought prone areas for providing assured supply of fodder to live stock;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRIMULLAPPALLI RAMACHANDRAN) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Settiny up of National Poultry Development Board

2430. DR. NARREDDY THULASI REDDY : SHRI P. UPENDRA :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state: '

(a) whether Government propose to set up a National Poultry Development board on the lines of the National Dairy Development Board to coordinate various activities in the field of poultry development;

(b) if so, the details theereof ; and by when the Board is likely to be set up; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI K.C. LENKA) : (a) A prposal to set up National Poultry Development Board has been included in the 8th Five year plan.

(b) The details for the establishment of the proposed Board are being worked out.

(c) Does not arise.

उत्तर प्रदेश में सहकारी भाण्डागार परियोजनाएं

2431. श्री ईश दत्त यादव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में यूरोपीयन आर्थिक समुदाय द्वारा सहायता प्राप्त सहकारी भाण्डागार परियोजना के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया है;

(ख) उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में यह सुविधा उपलब्ध करा दी गई है; और

(ग) इसके लिए प्रतिवर्ष कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था और प्रतिवर्ष उस लक्ष्य में कितनी उपलब्धि प्राप्त की गई थी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय से सहायता प्राप्त कोई भाण्डारण परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं होता।